

प्रपक

अमित सिंह नेगी
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

संयोजक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
भारतीय स्टेट बैंक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक कार्यालय
1-न्यू कैंट रोड, देहरादून।

सलाहकार (बैंकिंग)

देहरादून दिनांक 21 नवम्बर, 2015

विषय:- भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं/विषयों की प्रगति समीक्षा हेतु सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 18 नवम्बर, 2015 समय 03.00 बजे का कार्यवृत्त।

महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं/विषयों की प्रगति समीक्षा हेतु सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 18 नवम्बर, 2015 सॉय 03.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया समस्त बैंकों को कार्यवृत्त अग्रसारित कर पुष्टि शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्या- 575 /सी0एम0आर/स0वि0(बै0)/2015 एवं तददिनांक

- प्रतिलिपि 1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आंयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ
3. निजी सचिव, सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन को सचिव वित्त महोदय के अवलोकनार्थ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जी0एम0वी0एन0परिसर, राजपुर रोड, देहरादून।
5. अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, वित्त (बैंकिंग प्रभार), उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड
12. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
13. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि0।
14. सुश्री अनन्ता मिश्रा, स्टेट रिसोर्स पर्सन, यू0आई0डी0ए0आई0, एन0आई0सी0 परिसर, सचिवालय देहरादून।
15. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं/विषयों की प्रगति समीक्षा हेतु सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 18 नवम्बर, 2015 समय 03.00 बजे का कार्यवृत्त।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं/विषयों की प्रगति समीक्षा हेतु सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 18 नवम्बर, 2015 समय 03.00 बजे सम्पन्न हुई जिसमें अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन, अपर सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, पोस्टल विभाग, एन0आई0सी0, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, एग्रीकल्चर इंशोरेन्स कम्पनी, यू0आई0डी0ए0आई0 तथा प्रमुख बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है:-

1. कृषि भूमि पर ऑन लाईन बैंक प्रभार अंकित किया जाना : श्री मदन मोहन, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि कृषि भूमि पर ऑन लाईन बैंक प्रभार अंकित किये जाने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा तैयार की गई Web Application <http://agriloan.uk.gov.in> को Public Domain में NIC द्वारा Host किया जा चुका है तथा उक्त Application को तहसील विकासनगर एवं डोईवाला में Pilot आधार पर भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को सन्तुष्टि प्रमाण पत्र स्वरूप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। श्री अमित सिंह नेगी, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को निर्देशित किया गया कि Web Application के प्रयोग से सन्तुष्टि की दशा में, सन्तुष्टि प्रमाण पत्र स्वरूप पत्र शीघ्र संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को प्रेषित करें ताकि 01 दिसम्बर, 2015 से पूर्ण राज्य में सभी बैंकों के प्रयोग हेतु Web Application को उपलब्ध कराया जा सके। (कार्यवाही : पंजाब नेशनल बैंक/तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड/सलाहकार वित्त, बैंकिंग)
2. बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों को ऑन लाईन दर्ज किया जाना : बैंकों द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्रों को राजस्व विभाग के वेबपोर्टल पर ऑन लाईन दर्ज किये जाने हेतु राजस्व बोर्ड के स्वामित्व में एन0आई0सी0 द्वारा साफ्टवेयर का निर्माण किया जाना है। श्री मदन मोहन, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि Web Application तैयार करने के लिये वॉंछित विवरण पत्रांक एन0आई0सी0/यू0एस0यू0/2015 दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध करवा दिये गये हैं, कार्य निष्पादन के लिये आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून की स्वीकृति अपेक्षित है। श्री अमित सिंह नेगी, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्टाफ आफिसर, राजस्व बोर्ड, उत्तराखण्ड को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। (कार्यवाही : राजस्व बोर्ड, उत्तराखण्ड/तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0/सलाहकार वित्त, बैंकिंग)
3. प्रधानमंत्री जन-धन योजना : संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अन्तर्गत राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 20,56,975 हाउस होल्ड्स में से 20,56,687 हाउस होल्ड्स के खाते बैंकों द्वारा खोले जा चुके हैं तथा शेष 288 खाते खोलने का कार्य शीघ्र की पूर्ण कर लिया जायेगा। श्री अमित सिंह नेगी, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में सभी ग्रामीण हाउस होल्ड्स के बैंक बचत खाते, बैंकों द्वारा खोल दिये जाने के आँकड़ों पर शंका व्यक्त की गई। श्रीमति के0एस0 ज्योत्सना, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकरण की केस स्टडी कराने का सुझाव दिया गया जिसके लिये श्री अमित सिंह नेगी, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड द्वारा संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को जिला टिहरी में घनसाली अथवा गुत्तु ब्लाक तथा उत्तरकाशी में मोरी ब्लाक की केस स्टडी, वहाँ कार्यरत बैंकों से इतर किसी

अन्य बैंक अधिकारियों से करवाकर 30 नवम्बर, 2015 तक स्टडी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। केस स्टडी में स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिये सम्बंधित जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने हेतु सलाहकार वित्त, बैंकिंग को निर्देशित किया गया। स्टडी रिपोर्ट में गाँव का नाम, खाता धारक का नाम, बैंक का नाम जिसमें खाता खोला गया है, आधार कार्ड है या नहीं, पास बुक है या नहीं, रू-पे डेबिट कार्ड है या नहीं तथा खाता धारक के हस्ताक्षर आदि का समावेश करने हेतु निर्देशित किया गया। (कार्यवाही : जिलाधिकारी, टिहरी एवं उत्तरकाशी/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/सम्बंधित अग्रणी जिला प्रबन्धक, अग्रणी बैंक/सलाहकार वित्त, बैंकिंग : प्रगति 30 नवम्बर, 2015 तक अपेक्षित)

4. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : योजना अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिनोंक तक कुल 10,56,305 व्यक्तियों का पंजीकरण किया जा चुका है। श्री अमित सिंह नेगी, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा योजना की धीमी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया गया उनके द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकृत होने वाले प्रत्येक लाभार्थी की बीमा प्रीमियम की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है। संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया कि अग्रणी जिला प्रबन्धक, अग्रणी बैंक को स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त कर शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करायी जाये तथा पंजीकरण में आ रही समस्याओं को, यदि आवश्यक हो, तो शासन के संज्ञान में लाया जाये। (कार्यवाही : समस्त-जिलाधिकारी/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/अग्रणी जिला प्रबन्धक, अग्रणी बैंक)

5. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : योजना अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिनोंक 17 नवम्बर, 2015 तक 3,47,587 व्यक्तियों का पंजीकरण किया जा चुका है। धीमी प्रगति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया तथा इसमें वृद्धि हेतु संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। (कार्यवाही : संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/अग्रणी जिला प्रबन्धक, अग्रणी बैंक)

6. अटल पेंशन योजना : योजना अन्तर्गत दिनोंक 17 नवम्बर, 2015 तक 6,821 व्यक्तियों का पंजीकरण बैंकों द्वारा किया जा चुका है। योजना अन्तर्गत और अधिक पंजीकरण कराने हेतु सभी बैंकों को संयुक्त प्रयास करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। (कार्यवाही : संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/अग्रणी जिला प्रबन्धक, अग्रणी बैंक)

7. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : योजना अन्तर्गत रु0 1610.12 करोड़ के वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष दिनोंक 31.10.2015 तक रु0 393.2 करोड़ ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर श्री अमित सिंह नेगी, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया व सभी बैंकों से लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई। श्रीमति के0 एस0 ज्योत्सना, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा कोशल विकास के तहत प्रशिक्षित किये गये उद्यमियों के समतुल्य मुद्रा योजना के भौतिक लक्ष्य निर्धारित करने का भी सुझाव दिया गया, उनके द्वारा जिले की डी0सी0सी0/डी0एल0आर0सी0 की बैठकों में पी0एल0पी0 (Potential link plan) की समीक्षा न किये जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया तथा डी0सी0सी0/डी0एल0आर0सी0 की बैठकों में पी0एल0पी0 (Potential link plan) की समीक्षा आवश्यक रूप से किये जाने हेतु बैंकों को निर्देशित किया गया ताकि ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जा सके जिसमें बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जा सकता है। (कार्यवाही : संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, अग्रणी बैंक/समस्त बैंक/जिला उद्योग केन्द्र)

8. आधार कार्ड जारी किया जाना व आधार कार्ड की बैंक खातों में सीडिंग की प्रगति समीक्षा : सुश्री अनन्ता मिश्रा, स्टेट रिसर्स पर्सन, यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य की लगभग 1.01

करोड़ जनसंख्या में से 75 प्रतिशत का आधार कार्ड जारी किया जा चुका है तथा 82 प्रतिशत का पंजीकरण किया जा चुका है। शेष 18 प्रतिशत में से अधिकांश 0-18 वर्ष की आयु सीमा में होने की सम्भावना व्यक्त की गई जिसके लिये यू0ए0डी0ए0आई0 द्वारा स्कूलों में कैम्पों के माध्यम से इस आयु वर्ग के आधार कार्ड जारी करने का कार्य सन्तोषजनक रूप में किया जाना अवगत कराया गया। श्री अरूणेंद्र सिंह चौहान, अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि 0 से 5 वर्ष की आयु के मध्य आने वाले बच्चों के आधार कार्ड बनाने के समय उनके अभिभावक का होना आवश्यक है अतः इस आयु वर्ग के पंजीकरण में आधार टीम के सदस्यों को परेशानियाँ आ रही हैं। श्री अनुज शुक्ला, प्रतिनिधि पोस्टल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आधार कार्ड सामान्य डाक से प्रेषित किये जाते हैं अतः उनकी डिलीवरी का उनके विभाग के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है तथापि उन्होंने पुष्टि की कि किसी भी डाकघर में आधार कार्ड वितरण हेतु लम्बित नहीं हैं तथा सामान्य डाक से प्राप्त आधार कार्ड के वितरण को सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर विभाग द्वारा जॉच टीम के द्वारा विभिन्न डाकघरों का निरीक्षण किया जाता है। (कार्यवाही : स्टेट रिसोर्स पर्सन, यू0आई0डी0ए0आई0/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड/पोस्टल विभाग, उत्तराखण्ड/समस्त बैंक/सलाहकार वित्त, बैंकिंग)

9. फसल बीमा की प्रगति समीक्षा : डा0 एस0 प्रसाद, क्षेत्रीय प्रबन्धक, ए0 आई0 सी0, द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मौसम रबी 2015-16 से संबन्धित माडीफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की राज्य अधिसूचना शासन द्वारा जारी हो चुकी है तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना माह दिसम्बर 2015 के प्रथम सप्ताह में जारी होने की सम्भावना है। माडीफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम 2015-16 के अन्तर्गत अभी तक अच्छादन शून्य है। श्री अमित सिंह नेगी, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उद्यान विभाग से शीघ्र अधिसूचना जारी किये जाने की अपेक्षा की गई। सचिव वित्त महोदय द्वारा माडीफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम 2015-16 के अन्तर्गत अच्छादन शून्य होने के कारण रोष व्यक्त किया गया तथा बैंकर्स एवं सहकारिता विभाग को निर्देशित किया कि योजना के अन्तर्गत अच्छादन में गति लाने के लिये बैंक शाखाओं को निर्देश जारी किये जाय। श्री अमित सिंह नेगी, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि प्रचार-प्रसार पर अधिक से अधिक फोकस किया जाय। योजना के अनुसार जिले वार फसल बीमा के अन्तर्गत अच्छादित होने वाले कृषकों का प्राथमिक न्यूनतम Target का प्लान तैयार कर सभी जिलाधिकारियों को अतिशीघ्र प्रेषित किया जाय, जिससे कि अगामी VC में सभी जिलाधिकारियों के साथ अच्छादन बढ़ाने के लिए चर्चा की जा सके। जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति, जिसमें मुख्य कृषि अधिकारी सदस्य सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक, नार्बाड, जिला सहकारी बैंक, जिला अग्रणी बैंक, सहायक निबन्धक सहकारिता, तथा क्रियान्वयक अभिकरणों के प्रतिनिधि सदस्य नामित किये गये हैं, की समयानुसार बैठक की जाय तथा योजना की समीक्षा कर बैंकों एवं सहकारिता विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाय जिससे कि अनिवार्य रूप से फसल गेहूँ के लिए दिये गये फसली ऋण का बीमा अच्छादन हो सके एवं फसल के नुकसान होने की दशा में कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

10. बैंकिंग सेवायें प्रदान करने हेतु 1397 सब-सर्विस एरिया में बी0एस0एन0एल0 द्वारा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना : श्री महेश सिंह निखुपा, डी0जी0एम0, बी0एस0एन0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 216 सब-सर्विस एरिया में बी0एस0एन0एल0 द्वारा ब्रॉड बैंड/वाई मेक्स की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा इसकी सूची संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को प्राप्त हो गयी है। श्रीमति के0 एस0 ज्योत्सना, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि बी0एस0एन0एल0 द्वारा 216 एस0एस0ए0 में उपलब्ध कराई गई कनेक्टिविटी की, सम्बंधित बैंक, क्षेत्र विशेष में जाकर जॉच कर लें यदि बी0सी0 द्वारा बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के लिये कनेक्टिविटी पर्याप्त है तो इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करना आरम्भ करें तथा इसकी पुष्टि संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति व भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

11. जमा कर्ताओं के हित संरक्षित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 टी0 एवं 58 ई0 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी किया जाना : श्री अजय सिंह रौतेला, अपर सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में जमा कर्ताओं के हित संरक्षित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 टी0 एवं 58 ई0 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है तथा अगामी केबिनेट में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। (कार्यवाही : अपर सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन)

12. उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम 2005 की नियमावली जारी किये जाने विषयक : सलाहकार वित्त, बैंकिंग द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम 2005 की नियमावली पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा अधिसूचना जारी कराने की प्रारम्भिक कार्यवाही आज दिनांक 18.11.2015 को पूर्ण कर ली जायेगी। (कार्यवाही : अनुभाग अधिकारी, वित्त-1, उत्तराखण्ड शासन/सलाहकार वित्त, (बैंकिंग),

13. भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर आधारित मानकीकृत ई-भुगतान एवं ई-प्राप्ति सुविधा के माध्यम से सरकारी भुगतान एवं प्राप्ति की प्रगति समीक्षा : श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव, वित्त/अपर निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर आधारित मानकीकृत ई-भुगतान एवं ई-प्राप्ति सुविधा को राज्य में शुरू किये जाने की कार्यवाही अन्तिम चरणों में है तथा शीघ्र ही यह सुविधा, अधिकतम एक सप्ताह के भीतर, राज्य में शुरू किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रौद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार के अग्रणी प्रयास किये जाने के व्यापक प्रचार-प्रसार को, अन्य राज्य की भांति, प्रसारित किये जाने की आवश्यकता की भी अपेक्षा सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन से की गयी। (कार्यवाही : सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन/अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन/निदेशक, कोषागार/भारतीय रिजर्व बैंक)

14. अन्य विषय : संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा शासन से अनुरोध किया गया कि शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन त्रैमास में 33-33 प्रतिशत के आधार पर दिसम्बर, 2015 तक पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र सम्बंधित विभागों द्वारा चयन उपरान्त बैंकों को प्रेषित कराने का कष्ट करें ताकि समय रहते लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति की जा सके।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(अमित सिंह नेगी)

सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन

०६.११.१५